भारत में नवोन्मेषी उद्यम (स्टार्टअप्स) किस प्रकार उद्यमिता, नवाचार तथा रोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं? उनकी कार्यप्रणाली में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा उन चुनौतियों को पराजित करने हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए।
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) [GS3 ECONOMY-UPSC 2026]

How are startups in India promoting entrepreneurship, innovation and employment? Discuss the global and domestic challenges in their working and suggest suitable measures to overcome these challenges. (Answer in 250 words) 15 marks

भारत में नवोन्मेषी स्टार्टअप्स: संक्षिप्त रूपरेखा

➢ **टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?**

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगार सृजन, स्वदेशी तकनीक तथा विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास में स्टार्टअप्स की भूमिका को समझना आवश्यक है।

➢ **प्रश्न के कीवर्ड्स**

- नवोन्मेषी उद्यम
- उद्यमिता, नवाचार तथा रोजगार
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व डीप-टेक
- कार्यप्रणाली

➢ **प्रस्तावना**

'स्टार्टअप इंडिया' पहल (2016) के बाद भारत 1.6 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है।

➢ **मुख्य भाग**

1. उद्यमिता, नवाचार तथा रोजगार को प्रोत्साहन
   - समावेशी व विकेंद्रीकृत उद्यमिता
   - स्वदेशी एवं विघटनकारी नवाचार
   - व्यापक रोजगार सृजन
2. भारतीय स्टार्टअप्स की कार्यप्रणाली
   - समस्या-आधारित विचार
   - बहु-स्तरीय पूँजी संरचना:
   - असेट-लाइट व एजाइल मॉडल:
3. स्टार्टअप्स की कार्यप्रणाली में चुनौतियाँ
   - वैश्विक चुनौतियाँ:
   - घरेलू चुनौतियाँ:

➢ **आगे की राह**

- R&D और डीप-टेक पर ध्यान:
- 'रिवर्स फ्लिपिंग' व GIFT City:
- माँग-संचालित सरकारी खरीद:
- टियर-2/3 हब व कौशल निर्माण: छोटे शहरों में 'क्षेत्रीय नवाचार हब' बनाना तथा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स (AIC) को IITs/उद्योगों से जोड़ना।

➢ **निष्कर्ष**

भारतीय स्टार्टअप्स केवल व्यावसायिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि भारत को 'सेवा-आधारित' से 'नवाचार-संचालित ज्ञान एवं विनिर्माण अर्थव्यवस्था' में बदलने के मुख्य इंजन

भारत में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के लॉन्च के बाद से देश का नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का वर्ष 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर वर्तमान में 38वें स्थान पर पहुँचना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है।

<u>उद्यमिता, नवाचार तथा रोजगार को प्रोत्साहन</u>

(A) समावेशी एवं विकेंद्रीकृत उद्यमिता

- **टियर-2 एवं टियर-3 शहरों का सशक्तिकरण:** कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग 45%-50% अब छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों से उभर रहे हैं।

  उदा: देहात एवं निंजाकार्ट जैसे एग्री-टेक मंचों ने कृषि आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाकर ग्रामीण युवाओं में कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा दिया है।
- **सामाजिक एवं महिला उद्यमिता:** स्टैंड-अप इंडिया योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति व महिलाओं को ₹1 करोड़ तक का ऋण) और 'वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म' के कारण 48% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक/संस्थापक है।

  उदा: नायका एवं मामाअर्थ जैसी कंपनियों ने महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता की नई मिसाल कायम की है।

(B) स्वदेशी नवाचार

Result Mitra
IAS-PCS Institute

- **डीप-टेक और बौद्धिक संपदा का विकास:** निधि -प्रयास 2.0 और IndiaAI मिशन जैसी पहलों के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक प्रोटोटाइप में बदला जा रहा है।

  उदा: अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा विश्व का पहला 3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन ('अग्निबाण') विकसित करना और स्पेस-टेक में निजी नवाचार को नेतृत्व देना।
- **क्षेत्रीय विविधता और DPI पर आधारित नवाचार:** सेमीकंडक्टर, डिफेंस-टेक, क्लीन-टेक और फिनटेक क्षेत्र में UPI तथा ओएनडीसी जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग कर नवीन समाधान तैयार किए जा रहे हैं।

  उदा: रेज़रपे और फ़ोनपे द्वारा वित्तीय समावेशन को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना।

(C) गुणवत्तापूर्ण एवं व्यापक रोजगार सृजन

- **तकनीकी व गैर-तकनीकी कार्यबल का समावेशन:** स्टार्टअप्स न केवल उच्च-कुशल इंजीनियरों को बल्कि विपणन, मानव संसाधन और संचालन क्षेत्रों में भी व्यापक रोजगार दे रहे हैं।
- **गिग इकोनॉमी एवं असंगठित क्षेत्र का एकीकरण:** त्वरित वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्स ने अकुशल या अर्ध-कुशल कार्यबल को व्यवस्थित आजीविका प्रदान की है।

  उदा: ज़ोमैटो, स्वीगी तथा ब्लिंकिट जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स लाखों डिलीवरी पार्टनर्स को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आजीविका से जोड़ रहे हैं।

<u>भारतीय स्टार्टअप्स की कार्यप्रणाली</u>

भारतीय स्टार्टअप्स पारंपरिक व्यवसायों की तुलना में **लचीलेपन, प्रौद्योगिकी और तेजी से स्केलेबिलिटी** पर आधारित कार्यप्रणाली को अपनाते हैं।

1. विचारसृजन एवं समस्या का समाधान-: ये 'न्यूनतम व्यावहारिक उत्पाद' के सिद्धांत पर काम करते हैं। वे समाज या बाजार की किसी विशिष्ट समस्या की पहचान करते हैं और तकनीक का उपयोग कर उसका सस्ता समाधान पेश करते हैं।

उदा: देहात ने कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों की समस्या को पहचाना और किसानों को सीधे इनपुट व बाजार पहुँच प्रदान की।

2. फंडिंग एवं पूँजी जुटाना: स्टार्टअप्स बहु—स्तरीय फंडिंग मॉडल पर काम करते हैं-

- **सीड स्टेज:** एंजेल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसे सरकारी अनुदान।
- **ग्रोथ स्टेज:** वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स से विदेशी या घरेलू पूँजी।
- **मैच्योरिट:** शेयर बाजार में लिस्टिंग (जैसे नायका, ज़ोमैटो)।

उदा: फ़ोनपे और **रेज़रपे** ने UPI अवसंरचना का उपयोग कर त्वरित भुगतान सेवाएँ विकसित कीं।

3. परिचालन एवं व्यावसायिक मॉडल :

- **एजाइल मॉडल:** बाजार की माँग के अनुसार अपने उत्पाद या सेवा में तुरंत बदलाव करना।
- **गिग वर्कफ़ोर्स:** संपत्ति-रहित/हल्की रणनीति अपनाकर अनुबंध आधारित कार्यबल के साथ तेजी से विस्तार करना।

उदा: ज़ोमैटो और स्वीगी ने बिना खुद के रेस्तरां खोले केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म और डिलीवरी पार्टनर्स के नेटवर्क से कार्य किया।

Result Mitra
IAS-PCS Institute

<u>स्टार्टअप्स की कार्यप्रणाली में चुनौतियाँ</u>

(A) **वैश्विक चुनौतियाँ**

- **फंडिंग विंटर व वैश्विक मंदी:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च ब्याज दरों, भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण ग्रोथ-स्टेज और लेट-स्टेज वेंचर कैपिटल फंडिंग में भारी गिरावट आई है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** सेमीकंडक्टर, विशेष चिप्स और हार्डवेयर घटकों के आयात पर निर्भरता के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और ईवी स्टार्टअप्स का उत्पादन चक्र प्रभावित होता है।

(B) **घरेलू चुनौतियाँ**

- **कमर्शियलाइज़ेशन बाधाएँ व 'वैली ऑफ डेथ':** अधिकांश स्टार्टअप्स "कैश बर्न" नीति पर चलते हैं, जहाँ ग्राहक जुटाने के लिए भारी छूट दी जाती है। कई स्टार्टअप्स तकनीकी सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शुरुआती ग्राहक आधार और परिचालन नकदी प्रवाह की कमी के कारण 80-90% पहले 5 वर्षों में विफल हो जाते हैं।
- **निजी R&D खर्च की कमी:** भारत में सकल R&D खर्च GDP का मात्र ~0.64% है, जिसमें निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स का योगदान उन्नत विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।
- **विनियामक जटिलता व अनुपालन भार:** बहु-स्तरीय मंत्रालयी स्वीकृतियाँ, नगर निगम स्तर की नौकरशाही और बार-बार बदलते कर/श्रम कानून 'व्यापार सुगमता' के मार्ग में रुकावट बनते हैं।
- **कौशल अंतर:** जेनेरेटिव एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन और औद्योगिक स्वचालन जैसे उभरते क्षेत्रों में उद्योग-अनुकूल प्रतिभाओं की तीव्र कमी है।

<u>आगे की राह</u>

1. **R&D और डीप-टेक पर ध्यान:**
   सकल R&D खर्च को GDP के 0.64% से बढ़ाकर 2% किया जाए। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन तथा ₹1 लाख करोड़ के नवाचार कोष से AI, सेमीकंडक्टर और बायोटेक जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिले।
2. **'रिवर्स फ्लिपिंग' व GIFT City का उपयोग:**
   विदेशों में पंजीकृत भारतीय स्टार्टअप्स की भारत वापसी ('रिवर्स फ्लिपिंग') सुगम बनाई जाए। इसके लिए GIFT City में एकल-खिड़की मंज़ूरी और कर राहत दी जाए।
3. **माँग-संचालित सरकारी खरीद:**

सरकार स्टार्टअप्स की 'प्राथमिक ग्राहक' बने। GeM पोर्टल और iDEX (डिफेंस) के तहत न्यूनतम अनुभव व टर्नओवर की शर्तों में छूट देकर स्टार्टअप्स से सरकारी खरीद बढ़ाई जाए।

4. **टियर-2/3 शहरों का विकास व कौशल निर्माण:**
   स्टार्टअप इकोसिस्टम को छोटे शहरों तक पहुँचाने हेतु 'क्षेत्रीय नवाचार हब' विकसित हों। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को IITs/NITs तथा उद्योगों से जोड़कर AI व रोबोटिक्स में कुशल कार्यबल तैयार किया जाए।

निष्कर्षतः भारतीय स्टार्टअप्स केवल व्यवसाय नहीं हैं, बल्कि भारत को नवाचार और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्य इंजन हैं। यद्यपि फंडिंग विंटर और जटिल नियम कुछ बाधाएँ उत्पन्न करते हैं, फिर भी नीति आयोग के रणनीतिक मार्गदर्शन, 'एआई मिशन' और बेहतर फंडिंग व्यवस्था से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। सही नीतिगत सहयोग से स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Result Mitra
IAS-PCS Institute